

**Title:** Demand to control increasing rate of crimes, violation of human rights and atrocities against the women in Uttar Pradesh.

**श्री श्रीप्रकाश जयसवाल (कानपुर) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय अखबार में छपे एक समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। राज्य सभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्रालय में बताया है कि भारत में मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। मानवाधिकार उल्लंघन के 40,724 मामले दर्ज किए गए, इनमें से आधे 22043 मामले केवल उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे कितना ही दावा करती रहे कि वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधर रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पिछले तीन वॉर्षों में दर्ज किए मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर तमाम दावे धूल फांकते नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश में 1996-97 में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले 8600 दर्ज किए गए, 1997-98 में यह संख्या दुगुनी से भी ज्यादा यानि 17638 हो गई। 1998-99 में यह संख्या बढ़कर 22043 हो गई। यह स्थिति केवल मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की ही नहीं है, बल्कि राज्य में महिलाओं की स्थिति भी ऐसी ही है।

जहां 1997 में राज्य में महिलाओं के विरुद्ध 11,000 मामले दर्ज किए गए, यह 1998 में 17,000 हो गए और 1999 में 14,000 के करीब हो गए।...(व्यवधान)

महोदय, यह कोई साधारण मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं बढ़ रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं।...(व्यवधान) आप गृह मंत्रालय को इस बात के लिए निर्देशित करें कि इन सारे अपराधों पर अंकुश लगावाएं।...(व्यवधान)